# Newspaper Clips
## November 22-23, 2016

## November 23

Pioneer ND 23.11.2016 P-13

# MoU signed

ReNew Power Ventures, India's leading Renewable energy company exchanged a Memorandum of Understanding with the Indian Institute of Technology, Delhi (IITD) to set up a research facility on renewable energy. This exchange took place in the presence of the President of India Dr Pranab Mukherjee at the Rashtrapati Bhavan. The MoU is aimed at encouraging and nurturing talent in the field of renewable energy at the IIT Delhi campus thereby encouraging opportunities for academic research to advance India's fast growing renewable energy sector.

Under the MOU, ReNew Power and IITD will establish a Chair in the area of Renewable Energy and Storage with representatives from both the entities. The collaboration will jointly propose research and training programmes for representatives of both ReNew and IIT Delhi to lead or participate in.

Several activities around research and policy advocacy are planned under the initiative wherein the centre will be providing advice papers and status reports for the Government of India and multilateral organisations on renewable energy policy matters as a part of its objective. Academic programmes for undergraduate, graduate and PHD students from a leading institute such as IITD through ReNew's research centre will not only provide numerous opportunities for prospective renewable energy scholars but also develop a thought process around India's position as a rising renewable energy nation worldwide.

Hindustan ND 23.11.2016 P-15

# 'जेईई मेन 2017' का फार्म बिना आधार नहीं भर सकेंगे

कानपुर | वरिष्ठ संवाददाता

**प्रवेश परीक्षा**

- एनआईटी, आईआईटी और सीएफटीआई में प्रवेश का मामला
- सीबीएसई कराता है जेई मेन, दो अप्रैल, 2017 है परीक्षा

भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईआईटी), राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (एनआईटी) और अन्य केन्द्र पोषित संस्थान (सीएफटीआई) में प्रवेश के लिए होने वाली 'जेईई मेन 2017' का फॉर्म छात्र बिना आधार के नहीं भर सकेंगे। आईआईटी में प्रवेश के लिए छात्र जेईई एडवांस्ड के लिए क्वॉलीफाई करते हैं। जेईई मेन दो अप्रैल, 2017 को होगा।

केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) जेईई मेन का आयोजन करता है। पहली दिसंबर को इसका विस्तृत शेड्यूल जारी किया जाएगा। इसी दिन से ऑनलाइन फॉर्म भरे जा सकेंगे। यह फॉर्म 02 जनवरी 2017 तक भरे जा सकेंगे। शुल्क का भुगतान 03 जनवरी 2017 तक किया जा सकेगा।

**विवरण का मिलान होगा :** ज्वॉइन्ट एडमिशन बोर्ड (जैब) के अधिशाषी निदेशक के अनुसार भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) के जारी आधार कार्ड के नंबर के बिना अब जेईई मेन 2017 का फॉर्म नहीं भरा जा सकेगा। जेईई मेन के फॉर्म पर आधार नंबर, नाम, जन्म तिथि और जेंडर डालना होगा। विवरण फॉर्म में भरा जाएगा।

Nav Bharat Times ND 23.11.2016 P-5

# JEE मेन : 1 दिसंबर से वेबसाइट पर हर जानकारी

■ प्रमुख संवाददाता, नई दिल्ली

**स्टूडेंट्स का आधार कार्ड जरूरी**

■ जेईई एडवांस्ड 21 मई को होगा। इस बार इसे आईआईटी मद्रास कंडक्ट करेगा।

■ इस बार पेपर 1 में पॉजिटिव स्कोर करने वाले टॉप 2,20,000 कैंडिडेट एडवांस्ड के लिए चुने जाएंगे।

■ इस एग्जाम के क्राइटेरिया के हिसाब से यह एग्जाम दो बार ही दिया जा सकता है।

आईआईटी जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन (जेईई) मेन एग्जाम 2017 की सभी जानकारी 1 दिसंबर को वेबसाइट में मौजूद होगी। 2 अप्रैल 2017 को ऑफलाइन एग्जाम होगा और 8-9 अप्रैल को ऑनलाइन एग्जाम होगा है।

जेईई एग्जाम के लिए ऑनलाइन एप्लिकेशन प्रोसेस 1 दिसंबर को शुरू होगा। अप्लाई करने की लास्ट डेट 2 जनवरी होगी, फीस 3 जनवरी 2017 तक भरी जा सकती है। इस एग्जाम में क्राइटेरिया में इस बार कुछ बदलाव हैं। एचआरडी मिनिस्ट्री के फैसले के मुताबिक इस बार से जेईई मेन एग्जामिनेशन को रैंक कैलकुलेशन में 12वीं के मार्क्स को कोई वेटेज नहीं दी जाएगी। साथ ही, सभी आईआईटी/एनआईटी/आईआईआईटी और सेंट्रल से फंडेड टेक्निकल इंस्टिट्यूट के लिए क्वॉलिफाई करने के लिए 12वीं के एग्जाम में मिनिमम 75% मार्क्स होने चाहिए। एससी/एसटी कैंडिडेट्स के लिए यह 65% है।

इसके अलावा इस बार जेईई मेन 2017 के रजिस्ट्रेशन के लिए स्टूडेंट्स का आधार कार्ड जरूरी होगा। कैंडिडेट को अपना आधार कार्ड नंबर और वही नाम, डेट ऑफ बर्थ और जेंडर भरना होगा, जैसे यूआईडीएआई डेटा में हो। स्कूल डेटा से अगर आधार कार्ड का डेटा मैच नहीं करेगा, तो स्टूडेंट फॉर्म नहीं भर पाएगा, इसलिए मंत्रालय ने सलाह दी है कि स्टूडेंट्स जल्द आधार कार्ड में करेक्शन करवाएं।

जेईई मेन का पेपर 1 बीई/बीटेक ऑफलाइन एग्जामिनेशन 2 अप्रैल को होगा और पेपर 1 बीई/बीटेक ऑनलाइन एग्जामिनेशन 8 और 9 अप्रैल को होगा। जेईई मेन पेपर 2 बी ऑर्किटेक्चर/बी प्लानिंग ऑफलाइन 2 अप्रैल को होगा। एग्जाम की सभी जानकारी, सिलेबस, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एग्जामिनेशन फीस, देशभर के एग्जामिनेशन सेंटर, एलिजिबिलिटी के लिए स्टेट कोड, एप्लिकेशन, एडमिशन क्राइटेरिया, रिजर्वेशन पॉलिसी और बाकी सभी जरूरी तारीखों की जानकारी जेईई मेन की वेबसाइट jeemain.nic.in में 1 दिसंबर से डाल दी जाएगी। मंत्रालय के एक अधिकारी ने कहा जेईई मेन और जेईई एडवांस्ड दोनों का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अलग-अलग है, इसलिए स्टूडेंट्स दोनों के बारे में ध्यान से पढ़ें।

गुजरात, मध्य प्रदेश, हरियाणा, उत्तराखंड, नगालैंड, ओडिसा स्टेट और कुछ और इंस्टिट्यूशन ने जेईई मेन जॉइन किया है। इनका एडमिशन क्राइटेरिया इनसे जुड़ी अथॉरिटी तय करेंगी। जो स्टूडेंट्स इन राज्यों के इंस्टिट्यूशन में एडमिशन लेना चाह रहे हैं, उन्हें भी मंत्रालय ने जेईई मेन का ऑनलाइन फॉर्म भरने की सलाह दी है। पहले इसके लिए राज्य स्तर पर एग्जाम होते थे।

जेईई एडवांस्ड के लिए जेईई का पेपर 1 बीई/बीटेक है। सभी आईआईटी के अंडरग्रैजुएट कोर्सेज के लिए एडवांस्ड एग्जाम जरूरी है। जेईई एडवांस्ड 21 मई को होगा। इस बार इसे आईआईटी मद्रास कंडक्ट करेगा।

इस बार जेईई पेपर 1 में पॉजिटिव स्कोर करने वाले टॉप 2,20,000 कैंडिडेट (सभी कैटिगरी मिलाकर) एडवांस्ड के लिए चुने जाएंगे। इसके अलावा इस एग्जाम के क्राइटेरिया के हिसाब से यह एग्जाम दो बार ही दिया जा सकता है।

## IIT-JEE (Advanced) exams to be held in six foreign countries

http://timesofindia.indiatimes.com/city/mumbai/IIT-JEE-Advanced-exams-to-be-held-in-six-foreign-countries/articleshow/55569783.cms

IIT Joint Admission Board (JAB) released the name of six foreign countries, including three SAARC nations, where the IIT-JEE (Advanced) will be held in 2017. Examination centres will be set up in Addis Ababa (Ethiopia), Colombo (Sri Lanka), Dhaka (Bangladesh), Dubai (UAE), Kathmandu (Nepal) and Singapore. Based on their performance in the exam, students can select IITs for undergrad courses. Earlier, it was expected that the entrance exam to the premier institutions would be conducted for the first time in all SAARC nations, except Pakistan.

Hindustan Times ND 23.11.2016 P-8

# IITs seek relaxation of ₹24k cash withdrawal limit

Neelam Pandey

NEW DELHI: After the government's demonetisation move, the Indian Institutes of Technology (IITs) too are feeling the heat.

Some of them have approached the HRD ministry seeking relaxation from the cash withdrawal limit of ₹24,000 per week as they have to spend substantial amount on maintenance of their huge campuses on a daily basis.

According to sources, cash crunch has affected the maintenance work on the campuses.

"IITs conduct conferences and workshops on a daily basis which are attended by thousands of students and faculty members. These are fixed in advance and they are likely to get affected due to the restriction on cash withdrawal," said a source. There are 23 IITs in the country. A number of them incur an expenditure of over ₹1 lakh every day.

The IITs have requested the HRD ministry to take up the issue with the finance ministry.

A senior HRD official said they will examine the issue and decide whether to take it up with the ministry.

IITs have informed the ministry that the cash withdrawal restrictions will affect the scale and volume of work that is undertaken at these institutes, said officials.

"The cash withdrawal limit set by the RBI will result in total dislocation of the activities undertaken by IITs," said a source.

A number of experts and industry insider maintained that the Centre's decision to withdraw high-value bank notes will also affect education institutions that charge capitation fee for admissions.

Indian Express ND 23.11.2016 P-9

# IIT-Kharagpur requests relaxation in withdrawal limit

EXPRESS NEWS SERVICE
NEW DELHI, NOVEMBER 22

IIT-KHARAGPUR has written to the HRD Ministry seeking relaxation in the weekly withdrawal limit citing difficulties faced in day-to-day functioning. The government has fixed the weekly withdrawal limit at Rs 50,000.

IIT-Kharagpur Registrar has written to Higher Education Secretary V S Oberoi requesting exemption from this limit.

Sources said that the HRD Ministry may soon write to the Finance Ministry to communicate the difficulties being faced by universities and institutes and their need for more cash to carry out their administrative functions. It is not clear if the ministry will bat for just the centrally funded institutions or all institutes.

"We are a community of 20,000 people on campus. There are 40 academic units at IIT Kharagpur. The institute needs close to Rs 2 lakh in cash to carry out various functions. We are not used to operating completely in a cashless manner. Till we make that transition, we have requested the ministry to relax the withdrawal embargo," said an official of IIT Kharagpur, who did not wish to be identified.

Amar Ujala ND 23.11.2016 P-12

# गोवा में उठा बुनियादी सवाल

**दुनिया भर में अपनी साख जमा चुके आईआईटी की स्थापना जहां होगी, जाहिर है लोग खुश ही होंगे। लेकिन गोवा में ऐसा नहीं है। यहां के एक गांव लोलियम ने आईआईटी के लिए जमीन देने से इन्कार कर दिया है।**

वैश्विक स्तर पर अगर किसी भारतीय शिक्षा संस्थान की पहचान है, तो वह है आईआईटी। इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिए दुनिया भर में अपनी साख जमा चुके आईआईटी की स्थापना जहां होगी, जाहिर है लोग खुश ही होंगे। लेकिन गोवा में ऐसा नहीं है। यहां के एक गांव लोलियम ने आईआईटी के लिए जमीन देने से इन्कार कर दिया है। गांव वालों का कहना है कि जिस जगह आईआईटी बनाने का सरकार ने फैसला लिया है, वह सार्वजनिक और पवित्र भूमि है। जिसका इस्तेमाल मवेशी को चरने, गांव वालों के सार्वजनिक आयोजन मसलन पूजा, विवाह, स्थानीय त्योहार आदि के आयोजन के लिए होता है। नोटबंदी की खबरों की आपाधापी के बीच यह खबर कहीं दबी रह गई। गांव वालों की चिंता आईआईटी से गर्वोन्नत होने के बजाय अपनी सामाजिक और सार्वजनिक जिंदगी को लेकर कहीं ज्यादा है।

आजादी के बाद भाखड़ा नांगल बांध और भिलाई इस्पात कारखाना जब शुरू हुए थे, तब पंडित जवाहर लाल नेहरू ने इन्हें आधुनिक भारत का मंदिर कहा था। समाजवादी अर्थव्यवस्था के जरिये आजाद भारत की तस्वीर बदलने का सपना देखने वाले नेहरू का यह नजरिया ही कमोबेश आजतक आधुनिक सोच का पर्याय माना जाता है। लेकिन गोवा के लोलियम गांव ने इसे चुनौती दी है। इसके जरिये उसने विकासवाद और आधुनिकता के सामने बलि चढ़ती सामाजिकता और सार्वजनिक जिंदगी की समस्या को उभारा है। चूंकि सरकार के पास ताकत होती है, लिहाजा यह भी हो सकता है कि गोवा सरकार अपनी सत्ता की ताकत का

उमेश चतुर्वेदी

इस्तेमाल करे और जमीन का जबरिया अधिग्रहण करके आईआईटी को सौंप दे।

वैसे भी देश में जमीन के सबसे ज्यादा विवाद सार्वजनिक भूमि को ही लेकर हैं। मुंबई के टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस की एक शोध रिपोर्ट भी इसकी ही तस्दीक करती है। एक स्वतंत्र शोध समूह राइट्स एंड रिसोर्सेज इनीशिएटिव की अध्ययन रिपोर्ट का कहना है कि जनवरी 2000 से अक्तूबर 2016 के बीच देश में करीब 40 हजार करोड़ रुपये की योजनाओं का एलान हुआ। जिनमें से 86 फीसदी पर काम तो शुरू हो गया या पूरा हो गया, लेकिन 14 फीसदी योजनाएं जमीन विवाद के चलते फंस गईं। प. बंगाल में टाटा की सिंगूर परियोजना इसका चर्चित उदाहरण है।

आखिर ये विवाद क्यों उभरते हैं? इसकी बड़ी वजह यह है कि खेती या अन्य सार्वजनिक गतिविधियों के लिए इस्तेमाल होने वाली जमीनों को उद्योग, टाउनशिप या इंस्टीट्यूशन खड़ा करने के लिए अधिगृहीत किया जाना। उदारीकरण बेशक मौजूदा व्यवस्था को ज्यादा उद्योग और सेवा केंद्रित बना रहा हो, लेकिन हकीकत यह है कि जब मंदी आती है, तो बुनियादी अर्थव्यवस्थाएं ही लोगों के काम आती हैं। ग्रामीण अर्थव्यवस्था अब भी बुनियादी जरूरतों मसलन भोजन, पानी और कपड़ा को स्वावलंबी आधार पर पूरा करने की सोच पर केंद्रित है। लोलियम गांव के लोगों का एक तर्क यह है कि गांव के लोगों के लिए यहां भरपूर पानी नहीं है तो आईआईटी के हजारों छात्रों, प्रोफेसरों और दूसरे कर्मचारियों और उसके जरिए बढ़ी मंडी के लिए पानी कहां से आएगा।

सिंगूर आंदोलन के दौरान मशहूर लेखिका महाश्वेता देवी ने एक बड़ी बात कही थी कि उद्योगों के लिए बंजर और दलदली भूमि का अधिग्रहण क्यों नहीं हो सकता। कृषि योग्य भूमि का ही अधिग्रहण क्यों। महाश्वेता का वह सुझाव आज भी मौजूं है। गोवा की पंचायत ने यही संदेश देने की कोशिश की है।

**November 22**

Deccan Herald ND 22.11.2016 P-3

# JNU in self-promotion with Jan Jan Jnu programme

**NEW DELHI, PTI:** Jawaharlal Nehru University, which has been at centre of controversies in recent months on Monday organised an open day "Jan Jan JNU" for school children to work on the varsity's image and inform them about the university's contribution to various fields.

Around 800 students from 11 schools in the national capital where different departments had set up their respective stalls acting as information centre for prospective students and also detailed their achievements. "Universities should not remain as ivory towers. They should connect with the society. The main objective of Jan-Jan JNU is precisely this," JNU Vice Chancellor M Jagadesh Kumar said.

IIT Delhi Director V Ramagopal Rao emphasised on the need to inquisitive for students.

The students were also shown a movie about inception and development of JNU and were led through a range of exhibits followed by three parallel sessions on Mind Mapping and basic introduction to Indian sign languages, animation film on Panchantantra and a documentary from School of Languages. The varsity has been hogging limelight for negative reasons including a journal calling the varsity den of anti-nationals and three of its students being arrested for sedition in connection with an event on campus during which anti-national slogans .

Nai Duniya ND 22.11.2016 P-2

# जेएनयू के छात्रों ने पेश किया पराली संकट का आसान समाधान

नई दिल्ली । ब्यूरो

[illegible]



[illegible]

### कार्बन डाई ऑक्साइड के खतरे से भी पर्यावरण का बचाव संभव

[illegible]

## जेएनयू में ओपन डे की नई परंपरा शुरू

नई दिल्ली । ब्यूरो

[illegible]

### छात्रसंघ ने किया विरोध

[illegible]

Rajasthan Patrika ND 22.11.2016 P-2

# कलक्टर बनना चाहते हैं आईआईटी के छात्र

पत्रिका न्यूज़ नेटवर्क

rajasthanpatrika.com

मुंबई. देश और दुनिया में आईआईटी क्वालिटी एजुकेशन और बेहतर प्लेसमेंट के लिए जाना जाता है। लेकिन, अब बड़ी संख्या में छात्र नौकरी के लिए प्लेसमेंट में हिस्सा लेने से परहेज कर रहे हैं। इनकी नजरें सिविल सेवा की परीक्षा पर हैं। ऐसे छात्र इंजीनियर बनने की जगह कलक्टर बनना चाहते हैं।

देशभर के तमाम आईआईटी संस्थानों में दिसंबर से प्लेसमेंट की प्रक्रिया शुरू होगी। कंपनियां टेस्ट और इंटरव्यू लेंगी लेकिन इस बार प्लेसमेंट के लिए पंजीकरण कराने वाले छात्रों की संख्या में कमी आई है। सभी आईआईटी संस्थानों में इस संख्या में 28 फीसदी की गिरावट देखी गई है। आईआईटी बॉम्बे के 1800 में से सिर्फ 300 छात्रों ने पंजीकरण नहीं कराया।

### 28 फीसदी छात्रों ने प्लेसमेंट में बैठने से इनकार किया



### ये वजह बताई

आईआईटी मद्रास के 1500 छात्रों में से 200 ने नौकरी की चयन प्रक्रिया से खुद को अलग रखा है। ऐसे छात्रों ने लिखित में संस्थान को वजह बताई है। अधिकतर छात्रों ने कहा कि वे अब सिविल सेवा की तैयारी करेंगे। आईआईटी बॉम्बे के कैमिकल इंजीनियरिंग के अंतिम वर्ष के छात्र शरदुल वैद्या कहते हैं कि मैं करियर में स्थिरता चाहता हूं और यही वजह है कि मैंने इस साल प्लेसमेंट में हिस्सा लेने के फैसले को टाल दिया है।

Rajasthan Patrika ND 22.11.2016 P-2

### पांच सालों में बढ़ी है रुचि

ऑल आईआईटी प्लेसमेंट कमेटी के चेयरमैन प्रो. कस्तुबा मोहंती ने कहा कि पांच सालों के दौरान छात्रों की रुचि सिविल सेवा में बढ़ी है। उन्होंने कहा कि बहुत से छात्रों ने पिछले साल भी सिविल सेवा की परीक्षा दी थी। लक्ष्य एकेडमी के निदेशक अजीत पड़वाल कहते हैं कि सिविल सेवा की तैयारी की कोचिंग लेने वाले दो सालों में बढ़े हैं। इनमें बड़ी संख्या में आईआईटी के छात्र हैं। आईआईटी मद्रास प्लेसमेंट सेल के सलाहकार मनु संथनम कहते हैं कि सिविल सेवा के अलावा छात्रों की रुचि उच्च शिक्षा में बढ़ी है, जबकि स्टार्टअप में घटी है।

Tribune ND 22.11.2016 P-4

# 130 awarded degrees

TRIBUNE NEWS SERVICE

ROPAR, NOVEMBER 21

A total of 130 students were given degrees during the annual convocation of IIT Ropar here on Monday. Prof Ashutosh Sharma, secretary, Department of Science and Technology, Government of India, was the chief guest on the occasion.

Director of the institute Sarit K Das said the institute had been focusing on problems being faced by the people of the region in the field of research. There was a grave problem of depleting underground water level in Punjab and Haryana for which IIT Ropar had started work to develop sensor-based irrigation system, he added.

Business Line ND 22.11.2016 P-6



# IIT-M report paints a healthy picture of start-up ecosystem

OUR BUREAU

Chennai, November 21

An IIT-Madras report on the entrepreneurial ecosystem in the country reaffirms that the start-up world is active and buzzing — there are more individuals turning angel investors, the amount the angels invest is going up, more start-ups are being founded and many more of these are getting funded. However, the percentage of ventures that attract subsequent rounds of funding has dropped significantly.

Titled 'India Venture Capital and Private Equity report: Inspiration and momentum for the gladiators: a study and analysis of the start-up industry', the report by the Department of Management Studies highlights two concerns. One, the development of the ecosystem has been restricted to a few States and within these States, only to the capitals. "The velocity of trickling down to other cities has been very slow," it points out. Two, "the growth in the number of investors and the amount of investment has been significantly high, which cannot be sustainable in the long run."

Such exuberance, the report says, can have undesirable side effects. For instance, many naive investors can get attracted by the euphoria of investing in start-ups, without fully being aware of the risks involved. From a situation a few years ago, when founders and members of the industry complained of the lack of seed and early-stage funding, the pendulum has swung the other way now, says the report.

**Raises concerns over ventures being restricted to a few States, and sustainable investments**

Because of the "spray and pray" practice of some investors — that of making small investments but not showing the required commitment — these investors tend to move away from making such investments if they are disappointed by the outcome, resulting in dwindling investments in start-ups.

Analysing angel deals, the report reveals a continuous increase in the number of deals between 2008 and 2015 — from 103 deals in the 2006-10 period to 2,790 in 2013-15. "The fact that so many angels are making investments in start-ups has been one of the biggest changes in the entrepreneurial ecosystem in recent years," it adds.

During this period, the amount invested by angels grew from ₹36.8 crore in 2006-10 to ₹4,321.7 crore in 2013-15, while the number of angel investors increased from six in 2008 to 978 in 2015. Another development as far as angel investors go is the forming of networks, such as the Indian Angel Network, Mumbai Angels, Chennai Angels and the Keiretsu Forum, which is a global network of angel investors headquartered in the US and with chapters in different countries.

According to the report, the average investment in an angel round has increased nearly four times between 2009 and 2015, from ₹1.06 crore to ₹4.67 crore. The study also finds that the average age of the start-up at the time of receiving the angel funding has decreased markedly — from 4.77 years in 2008 to around half a year in 2015. As is to be expected, given the trend in the nature of start-ups, ventures in the software and internet services account for the largest number of angel deals, followed by internet market place and e-commerce, whose share has shown an increasing trend of late.

Analysing the trends in start-up funding from all sources — angels, angel networks and venture funds — the report says investment picks up slowly in each sector (possibly a period of learning and understanding for both the entrepreneur and the investor) and reaches a peak and tapers. "It is clearly evident that entrepreneurs have a better chance of getting funded during the growth period of the sector," the report says, and adds: "The sector that has bucked the trend has been the software and internet services sector."

**Start-up gap**

Clearly, Bengaluru, Mumbai and the National Capital Region lead in terms of start-ups getting funded, and over the years, the gap between these three cities and the others — Chennai, Hyderabad and Jaipur — has considerably increased. To ensure that the gap does not widen further, the report suggests that policy makers should identify components of the entrepreneurial ecosystem in cities such as Bengaluru that make more start-ups get funded.

Dealing with follow-on rounds of funding, the report says only one in every 875 start-ups that get founded, or a mere 0.11 per cent, is able to raise four or more rounds of funding. Out of the total start-ups that get founded, about 6 per cent have been part of an accelerator or incubation programme.

Analysing the trends in start-up funding from all sources, the report says investment picks up slowly in each sector, reaches a peak and tapers

# IIT Madras to develop multi-village microgrid models for efficient, green power supply

http://timesofindia.indiatimes.com/business/india-business/IIT-Madras-to-develop-multi-village-microgrid-models-for-efficient-green-power-supply/articleshow/55538932.cms

BENGALURU: IIT Madras recently said it will collaborate with industry to develop a more efficient, cheaper and cleaner way to ensure power supply to villages through the use of microgrids.

The government of India is looking at a generation capacity of 40 GW in the next five years through grid connected (GC) solar photovoltaic (PV) rooftops and small scale solar PV plants. And, IIT Madras and power and automation technology company ABB India will further this plan through a collaboration to develop a system that will operate multiple microgrids, with or without a grid connection, to transmit electricity reliably to small villages. This system will also enable the integration of individual solar PV rooftops to the microgrid of a village.

Such grid clusters are expected to have the capability of generating and using renewable energy locally from one kilowatt to a few hundred kilowatts. This inter-connection of microgrids with the existing distribution system will help reduce outages and also cut electricity costs.

The project scope includes microgrids of 20 to 100 kW capacity equipped with battery storage. Detailed studies and simulation of the various system components along with related control and optimization logics, protection criteria, monitoring and communication will also be undertaken.

"While India has set an ambitious target for solar energy generation, IIT Madras has been at the forefront in developing decentralized energy-efficient solar PV microgrid solutions tailored to meet India's urban, rural and off-grid power requirements," said Bhaskar Ramamurthi, Director of IIT Madras.

ABB India's managing director Sanjeev Sharma said the collaboration is the need of the hour.

"In a country as huge and diverse as India, it is important to design models of integration with power management and load balancing for proven microgrids technology with the existing grid infrastructure," added Sanjeev Sharma.

## Alloy Steels Plant collaborates with IIT Kharagpur under PM's Uchchatara Aviskar Yojna

http://economictimes.indiatimes.com/industry/indl-goods/svs/metals-mining/alloy-steels-plant-collaborates-with-iit-kharagpur-under-pms-uchchatara-aviskar-yojna/articleshow/55542544.cms

KOLKATA: Alloy Steels Plant (ASP), Durgapur – the alloy & special steels manufacturing arm of Steel Authority of India (SAIL) has entered into an agreement for collaboration with IIT Kharagpur. The agreement comes under the prime minister's 'Uchchatara Aviskar Yojna' (UAY), which is a panel of industry-sponsored, outcome-oriented research projects.

The association between the two institutions, ASP & IIT, Kharagpur will focus on technologydevelopment in the area of alternative iron making routes. The joint collaboration aims at accelerating the Research & Development in Sponge Iron production using off-grade iron ore and coal fines to convert waste to wealth. The project is expected to facilitate economical recycling of huge accumulation of unusable iron ore fines and coal fines available in SAIL mines. The project will be funded by the HRD ministry and steel ministry, apart from support from ASP, which is the industrial partner.

The project will involve setting up a pilot plant with a capacity of five tonne per day at ASP, Durgapur by IIT Kharagpur for joint research, while ASP will provide raw material and other inputs. The overall time frame for this UAY project will be three years.

The project has been captioned as 'Development of Rotary Hearth Furnace (RHF) Technology for Treating Off-Grade Iron Ore Fines of Indian Origin, including Magnetite Ore.'

Incidentally, ASP, Durgapur has emerged as a key producer of special steels for the country's strategic sectors like Defence & Railways among others. The plant has been focused on aggressive cost reduction in recent times to remain competitive in the face of sliding demand for alloy steels and low margins. The UAY project is expected to give ASP the much needed shot in the arm by way of enabling cost reduction. Analysts feel that the unit needs to be spruced up with some moderate investment directed towards upgrading its ageing facilities to remain competitive.

Hindustan Times ND 22.11.2016 P-8

# 13 out of 20 IIMs working without full-time directors

**NEW DELHI:** More than half of the 20 Indian Institutes of Management (IIMs) are functioning without a full-time director. The post of director in 13 IIMs, including Bangalore and Nagpur, are vacant, the Lok Sabha was informed on Monday. The others are Kozhikode, Amritsar, Sirmaur, Rohtak, Bodh Gaya, Ranchi, Sambalpur, Raipur, Udaipur, Visakhapatnam and Tiruchirappalli.

"However, the directors of the mentor IIMs are looking after the six new IIMs (Amritsar, Sirmaur, Bodh Gaya, Sambalpur, Nagpur and Visakhapatnam) till the appointment of regular directors," said minister of state for human resource development, Mahendra Nath Pandey, in a written reply.

He further said that for other IIMs, the tenure of the outgoing director has been extended or the institute's senior-most professor given additional charge of the post.

For IIM Kozhikode and IIM Udaipur, advertisements for the posts have been issued, he said, adding that for others a search-cum-selection committee has recommended a panel of names.

Sources said that appointments in key institutions, which include many Indian Institutes of Technology (IITs), are also stuck with the HRD ministry. **HTC**